**Periodic Meetings between M.Ps and District level officers**

1318. SHRI GOVINDRAO ADIK! Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to have periodic meetings between the Members of Parliament and the district level officers of his/her constituency to review the process of development work proposals of the Members under the scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The Committee of Privileges (Tenth Lok Sabha) in its Fifth Report has recommended that periodic meetings should be held between the Member of Parliament and district level officers of his/ her constituency to review the progress of development work proposed by Member under the scheme. This matter is under consideration of the Government.

(c) Does not arise.

**विद्युत नीति को प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाया जाना**

1319. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत नीति संबंधी पैकेज को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) बहुराज्यीय बड़ी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किन विशेष मानदंडों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) अनावश्यक मुकदमेबाजी और परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब को टालने के लिए कौन से प्रभावी उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) विद्युत नीति संबंधी पैकेज को प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाए जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचम्लानात्मक कमियों को दूर करने अधिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक समुपयोजन किया जाना, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए समुचित गुणवत्ता वाले कोयले की उचित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा विमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयनीकरण किया जाना शामिल है। विद्युत प्रणाली की तकनीकी हानियां कम करने हेतु स्कीमें आरंभ करने के अतिरिक्त, केन्द्रों तथा राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माणरत परियोजनाओं कम तीव्र गति से क्रियान्वयन किए जाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर निवेश किए जाने हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाने के अकेले सार्वजनिक क्षेत्र को काफी मुश्किलें आ रही है।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने वृहद् (मेगा) परियोजनाओं के रूप में 1000 मे.वा. तथा उससे अधिक क्षमता की बड़े आकार वाली ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है, जिनसे एक से अधिक राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जा सके। नीति में के॰वि॰प्रा॰ द्वारा ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और सम्पवर्तकों के चयन के लिए पावरग्रिड द्वारा उपाय तैयार करने तथा सम्पवर्तकों एवं राज्य बोर्डों के बीच पी॰पी॰ए॰ को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और के॰वि॰प्रा॰ इन परियोजनाओं की गहराई में मानिदरि कर रहे है और संबंधित और संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाकर समय पर सहायता प्रदान कर रहे है।

**Scheme cleared for supply of drinking water to Gujarat**

1320. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of each scheme cleared by the Central Government on the proposals submitted by the Government of Gujarat for drinking water scarcity-prone areas and in the flouride affected villages of Gujarat;

(b) the details of assistance provided so far or proposed to be provided for each scheme;

(c) the details of such schemes still pending with the Central Government for clearance; and

(d) by when the remaining schemes are likely to be cleared and communicated to the State Government?